

देशबन्धु

वर्ष – 37 | अंक –275 | भोपाल, मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ–8 | मूल्य – 3.00 रुपए

रानी दुर्गावती के मार्ग पर जनजातीय विकास का नया अध्याय

2

► सामाजिक प्रतिक्रिया का युद्धरोध
► बलों के पोषण में डिजिटलीकरण न बने बाधा

नवरात्रि में मास- मछली की दुकानें बंद रखने बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन

4

टेस्टइंडीज के खिलाफ भारत पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बुलंद इरादों से उतरेगा

6

7

सार-समाचार

भारत-यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास 'माउंटेन गार्डियन' शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'माउंटेन गार्डियन 2026' सोमवार से शुरू हो गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास 18 अक्टूबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, आपसी समझ और सहयोग बढ़ाना है। अभ्यास में पहाड़ी युद्ध पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास में दोनों देशों के कुल 92 सैन्यकर्मों हिस्सा ले रहे हैं। दोनों सेनाओं की बराबर भागीदारी है। भारतीय दल में भैरव बटालियन के जवान और यूएई के दल में माउंटेन इन्फैंट्री बटालियन के जवान शामिल हैं।

फ्रांस में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद 500 विद्यालय बंद

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा के स्तर में गिरावट को लेकर जारी छात्र आंदोलन के हिंसक होने के बाद सोमवार को देश भर के करीब 500 विद्यालयों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में दंगे को नियंत्रित करने वाली पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हुई तीखी झड़पों के बाद सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री एडुआर्ड गेफ्रे ने बताया कि सुरक्षा स्थितियाँ पूरी न होने के कारण लगभग 400 से 500 उच्च विद्यालयों में कक्षाओं को 'पूर्ण या आंशिक रूप से निर्लंबित' कर दिया गया है।

पटना की सड़कों पर उतरे दारोगा परीक्षा अभ्यर्थी

पटना, एजेंसी। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को एक बार फिर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार दारोगा अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) द्वारा मुख्य परीक्षा रह किए जाने के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को रद्द करने के निर्णय को वापस लेने और घोषित परिणाम को मान्य करने की मांग कर रहे थे। दारोगा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जेपी गोलंबर के पास जुटे और प्रदर्शन शुरू किया।

राहुल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए

भोपाल, देशबन्धु। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा कि वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उन्हें भेजे गए नोटिस वापस लिए जाने चाहिए। राहुल ने अपने पत्र में कहा कि सीमित पदों के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। इनमें कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, जबकि कई अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं भी दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि लंबे समय से इंतजार कर रहे कुछ अभ्यर्थी आयु सीमा के करीब पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता ने इस बात पर हैरानी जताई कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं, और तब भी इनकी बात सुनने के बजाय सरकार उन्हें नोटिस भेज कर डराने की कोशिश कर रही है। राहुल ने पत्र में लिखा कि इंदौर में छात्रों की गुंज कार्यक्रम के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने भर्ती में पदवृद्धि की मांग उठाई।

एसआईआर विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी टिप्पणी

फॉर्म-6 में बदलाव की हमने नहीं दी मंजूरी

► केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
► अंतरिम आदेश पारित करने से किया इनकार
► अदालत ने कहा, हम देखेंगे कि फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया

नई दिल्ली, एजेंसी।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निर्लंबित करने से जुड़ी याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। याचिकाओं में सीईसी ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। आरोपों को लेकर अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय्यमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने सोमवार को याचिकाओं पर सुनवाई की।

चुनाव आयोग ने दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन 'फॉर्म 6' के साथ जोड़े गए नए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। लेकिन सीजेआई सूर्य कांत ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के

फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया है।

कोर्ट अब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर आरोपों की जांच करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि आयोग के जवाब से यह सामने आता है कि ऐसे फैसले लिए गए थे, जिनके लिए आवश्यक सर्वसम्मति नहीं थी, तो कोर्ट उन फैसलों को वापस लेने या रद्द करने पर विचार कर सकता है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे।

नागरिकों के वोटिंग अधिकार खतरे में हैं: वकील

अदालत में वकील विकास सिंह ने कहा कि 2023 एक्ट से चुनाव आयोग का अधिकार बढ़ाया गया है। कुछ अंतरिम उपायों की जरूरत है। आयोग की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। विकास सिंह ने सुनवाई पूरी होने तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की शक्तियों को सस्पेंड करने या उनसे शक्तियाँ वापस लेने की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि नागरिकों के वोटिंग अधिकार खतरे में हैं और सीईसी पक्षपाती हैं। मेनका गुरुस्वामी ने इसी से जुड़ी एक दूसरी याचिका में 'फॉर्म 6' में किए गए बदलावों पर सवाल उठाए और एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी खामियों का आरोप लगाया। मेनका गुरुस्वामी ने अदालत में कहा कि हमने इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते देखे हैं। आज वैसी स्थिति नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। बेंच ने मेनका गुरुस्वामी से याचिका में की गई मांगों के बारे में सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों पर कायम हैं।

ध्यान भटकाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने जनता को किया सचेत

- अपनी मांगो से पीछे नहीं हटेगा विपक्ष
- चौथे दिन भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, देशबन्धु। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को पद से हटाने और एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष के सभी सांसद मंगलवार को संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करेंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्ष अपनी तीन मांगों से पीछे नहीं हटेगा। इसमें पहली यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें, दूसरी एसआईआर को रद्द किया जाए और तीसरी मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में पुलिस पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार नफीसा और उनकी बहन ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। नफीसा ने कथित मारपीट में शामिल पुलिस अधिकारियों के नाम बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए थाने और संबंधित स्थानों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

नफीसा ने बताया कि मारपीट की घटना में एसएचओ दिनेश कुमार और एसआई सोनम समेत अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका रही। उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग राहुल गांधी के सामने रखी। पत्रकारों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक होने से यह स्पष्ट हो

यह है कि चुनाव ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से कराए जाएं। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन सड़कों पर। उन्होंने अन्य संगठनों व सिविल सोसायटी के संघर्ष को भी अपना समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने जनता को सांकेतिक तरीके से चेतावनी भी दी है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच चौथे दिन सोमवार को भी दिल्ली में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक तरफ कांग्रेस की

सकेगा कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था और घटना में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे।

मुलाकात के दौरान महिला पत्रकारों ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार और मारपीट के आरोपों से जुड़े तथ्य राहुल गांधी को बताए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

महिला पत्रकारों ने राहुल से मिलकर बताई पुलिस की बर्बरता

गंभीर संवैधानिक संकट में है बांग्लादेश

शेख हसीना बोली, जनता को तय करना है देश का भविष्य

जिनेवा, एजेंसी। बांग्लादेश का भविष्य डर या ताकत के जरिए नहीं, बल्कि वहां के लोगों की स्वतंत्र और पूरी जानकारी के आधार पर दी गई राय से तय होना चाहिए। देश इस समय 'गंभीर संवैधानिक संकट' से जूझ रहा है। यह बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक सेमिनार में कही। हाल ही में जिनेवा में आयोजित इस सेमिनार का विषय था 'बांग्लादेश का संवैधानिक संकट: शिक्षा का अधिकार, मनमानी हिरासत और ट्रिब्यूनल के कथित तौर

प्रेस क्लब में हुए सेमिनार में बांग्लादेश की संवैधानिक व्यवस्था, कानून के शासन, मानवाधिकार, राजनीतिक भागीदारी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के भविष्य पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को वक्तुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि जुलाई और अगस्त 2024 की घटनाएं बांग्लादेश में शांति या खुशहाली लाने में नाकाम रही हैं।

राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने किया उग्र में 8 उम्मीदवारों को ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में दो महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार, धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव होगा। इन सभी सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है। इसकी वजह से इन सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक सीट खाली हुई है। यहां से तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रश्मिणी मल्लिक ने 16 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2032 तक था। इसी खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर तक है। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर शुक्रवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।

संवैदा आधार पर विशेषज्ञ सर्वगं अधिकारियों की नियुक्ति			
संविदा आधार पर निम्नलिखित पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कि जाते हैं.			
विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2026-27/24 (संविदा पद)			
पद का नाम	रिक्ति	आयु (31.07.2026 तक)	
		न्यूनतम	अधिकतम
उप उपाध्यक्ष (एनालिटिकल मार्केटिंग एंड कैपेन)	1	33	45
उप उपाध्यक्ष (डिजिटल मार्केटिंग)	2	33	45
कंटेन्ट विशेषज्ञ	1	25	40
विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2026-27/25 (संविदा पद)			
हेड सेल्य	1	40	52
केंद्रीय अनुसंधान दल (उत्पाद सीड)	2	30	45
प्रबंधक (व्यवसाय प्रक्रिया)	1	30	40
मरियोजना विकास प्रबंधक (प्रोग्रामिग)	1	25	40
सेटल अप्रिंशंस टीम (सीओटी) स्पेर्ट	1	30	40
पात्रता मानदंड (आयु, अनुभव, जॉब प्रोफाइल आदि), रिक्ति विवरण, आवश्यक शुल्क एवं अन्य विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings पर लॉग ऑन करें, जहाँ उपरोक्त विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध है. इसके साथ आवेदन को ऑनलाइन जमा करने और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु एक लिंक भी दी गई है. आवेदन करने और शुल्क भेजने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने एवं अन्य विवरणों के लिए विस्तृत विज्ञापन पढ़ें. कोई अन्य प्रश्नछाड़ करने के लिए कृपया "CONTACT US" -- "Post Your Query" लिंक के माध्यम से हमें लिखें, जो कि बैंक की वेबसाइट (https://sbi.bank.in/web/careers/post-your-query) पर उपलब्ध है.			
• आवेदन ऑनलाइन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की तिथि : 30.09.2026 से 21.10.2026 तक.			
स्थान: मुंबई		महाप्रबंधक (आरपी एंड पीएन)	
दिनांक: 30.09.2026			

www.deshbandhu.co.in | भोपाल | सागर | नर्मदापुरम | जबलपुर | सतना | रायपुर | बिलासपुर | नई दिल्ली

मुख्यमंत्री आज युवाओं से करेंगे संवाद

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव–2026 में प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इसका उद्देश्य युवाओं को नई दिशा, प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराना है। कॉन्क्लेव में प्रदेश से 20 हजार से अधिक युवा सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अवसरों की जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। डॉ. यादव युवाओं से संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और अपेक्षाओं को जानेंगे तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विकास पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस मौके पर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्द्र सिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे। कॉन्क्लेव में आईआईटी मुंबई और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ युवाओं को शिक्षा, तकनीकी विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। एम्स के मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबिन नैटियाल तथा कबीर कैफे द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेंगी। कॉन्क्लेव में 17 शासकीय विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। उच्च शिक्षा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, आयुष तथा पुलिस एवं साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न विभाग युवाओं को अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित योजनाओं, अवसरों और गतिविधियों से परिचित कराएंगे।

देवड़ा और टेटवाल ने सुनी समस्याएं, निराकरण के लिए निर्देश

भोपाल, देशबन्धु। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं मंत्री गौतम टेटवाल ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं एवं सुझावों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विभाग की कार्यवाई आवश्यक है, उन्हें शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। उप मुख्यमंत्री और मंत्री टेटवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। आमजन की जनसमस्याओं का समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

भीषण गर्मी ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़े

सुरेश एस डुमगर

जम्मू, देशबन्धु। कश्मीर में रविवार को असामान्य रूप से भीषण गर्मी पड़ी, कई मौसम स्टेशनों ने अक्टूबर के उच्चतम या लगभग उच्चतम तापमान दर्ज किए क्योंकि पारा मौसमी औसत से काफी ऊपर चढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अक्टूबर माह में शहर में दर्ज किया गया दूसरा सबसे अधिक तापमान है।

यह तापमान 2 अक्टूबर, 2008 को दर्ज किए गए पिछले अक्टूबर के उच्चतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। श्रीनगर में अक्टूबर का अब तक का सबसे अधिक तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस है, जो 2 अक्टूबर, 1931 को दर्ज किया गया था। काजीगुंड में तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने 1 अक्टूबर, 1985 को दर्ज किए गए पिछले अक्टूबर के रिकार्ड 31.2 डिग्री सेल्सियस को तोड़ दिया। तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री अधिक

कूनों में गूंजी चीतों की नई पीढ़ी की किलकारी

► **मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट चीते से जुड़ी टीम को दी बधाई**



भोपाल, देशबन्धु। मध्यप्रदेश के ख्योपुर स्थित कूनों राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत 5 अक्टूबर सोमवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई। भारतीय धरती पर जन्मी 32 माह की मादा चीता केजेपी-21 ने 5 स्वस्थ शавकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर अब 60 हो गई है, इसमें से 41 भारतीय धरती पर जन्में चीते शामिल है। भारत में जन्मी मादा चीता केजेपी-12 और मुछ्डी के बाद केजेपी-21 तीसरी मादा चीता है, जिसने भारतीय

धरती पर शавकों को जन्म दिया। यह उपलब्धि देश में चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों की सफलता और चीतों की नई पीढ़ी की विस्तार की दिशा में मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रोजेक्ट चीता से जुड़े वन्य अधिकारियों, पशु चिकित्सकों, मैदानी अमले, प्रबंधन टीम तथा सभी सहयोगियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नन्हें मेहमानों के आगमन से कूनों की धरती पर एक बार फिर वन्य जीव संरक्षण की नई उम्मीद ने जन्म लिया है।

रानी दुर्गावती के मार्ग पर जनजातीय विकास का नया अध्याय

खालवा में 6 सांदीपनि विद्यालय, हरसूद में 490 सीटर कन्या छात्रावास

भोपाल/ खंडवा, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वीरांगना रानी दुर्गावती के दिखाए मार्ग पर मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के विकास का नया अध्याय लिख रही है। रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर खंडवा जिले के हरसूद क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खालवा तहसील में 6 नए सांदीपनि विद्यालय बनाए जाएंगे। हरसूद में 490 सीटर कन्या छात्रावास बनेगा, जबकि करीब

161 करोड़ रुपए की लागत से 40 नए जनजातीय छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों में 34 करोड़ रुपए की लागत से रोटी मेकर मशीनें, वाटर कूलर और ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आश्रम स्कूलों के विकास के लिए 143 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने खंडवा में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हाइटेक नर्सरी और जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने की घोषणा की।

जनजातीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़े कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। करवानी उद्हन सिंचाई परियोजना पर भी तेजी से काम करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने खंडवा सहित 6 जिलों के 3 लाख 54 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 21.34 करोड़ रुपए

से अधिक की बोनस राशि अंतरित की। खंडवा वन मंडल की 56 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के 26,400 से अधिक हितग्राहियों को 4.58 करोड़ रुपए का काष्ठ लाभांश भी वितरित किया।

इस अवसर पर 52 गढ़ों के राजवंशजों का पहली बार सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने क हा कि रानी दुर्गावती का जीवन स्वाभिमान, नारी शक्ति, जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की प्रेरणा देता है। उन्होंने खंडवा जिले में करीब 143 करोड़



रुपए की लागत के 18 विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रीवा एवं मऊगंज में सेवा कार्यों में हुए शामिल, कहा किसानों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही सरकार

रीवा/भोपाल, देशबन्धु। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने सोमवार को रीवा एवं मऊगंज जिले के प्रवास के दौरान सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सेवा कार्यों में सहभागिता की। उन्होंने बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाकर संगठन को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को गोलियों से भूना गया था। भाजपा सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण करने के साथ हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब

परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प लिया है। गरीब के सिर पर पक्की छत हो, उसका बैंक खाता हो, उसे आयुष्मान योजना का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिले, उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएं से मुक्ति मिले और घर में शौचालय हो, इन संकल्पों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन



यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी जरूर तम दं व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया कहा आप बच्चों और उनके परिवारों की चिंता करें, क्योंकि आपके प्रयास आने वाली पीढ़ी के भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज और मजबूत भारत का

निर्माण करेंगे। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी संबोधित किया।

बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह, संभाग प्रभारी विजय दुबे, जिला प्रभारी शशांक श्रीवास्तव, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र मिश्रा, विधायक गिरीश गौतम, प्रदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विध्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखण्ड प्रताप सिंह, मृगेंद्र सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

10 विमानतल और सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे स्थायी हेलीपैड

प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार होगा

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विमानन सेवाओं और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नागरिकों का ताम्रान सामान्य से 6.7 डिग्री अधिक था, जिससे यह रिसार्ट में दर्ज किया गया दूसरा सबसे गर्म अक्टूबर का दिन बन गया। इस बीच, कोकरनाग में अक्टूबर के महीने का नया रिकार्ड तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 4 अक्टूबर, 2008 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री अधिक था। आरिफ कहते थे कि घाटी के स्टेशनों और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों दोनों जगह असामान्य रूप से उच्च तापमान का लगातार बने रहना वर्तमान स्थिति को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाता है। यह गर्मी ऐसे समय में आई है जब कश्मीर में तापमान में आमतौर पर शरद ऋतु के आगे बढ़ने के साथ लगातार गिरावट आने की उम्मीद होती है, और घाटी में ठंडक का प्रकोप अधिक स्पष्ट होने लगता है।

अक्टूबर में भी तप रहा कश्मीर

श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज

था। स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ ने कई स्टेशनों पर दर्ज किए गए तापमान को

गुलमर्ग में भी पारा 23.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

गुलमर्ग में भी असामान्य रूप से गर्म मौसम रहा, जहां पारा 23.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह तापमान पिछले दिन दर्ज किए गए अक्टूबर के उच्चतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। गुलमर्ग में अक्टूबर का रिकॉर्ड तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस है, जो 1 अक्टूबर, 2009 को दर्ज किया गया था। रंहवार का तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री अधिक था, जिससे यह रिसार्ट में दर्ज किया गया दूसरा सबसे गर्म अक्टूबर का दिन बन गया। इस बीच, कोकरनाग में अक्टूबर के महीने का नया रिकार्ड तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 4 अक्टूबर, 2008 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री अधिक था। आरिफ कहते थे कि घाटी के स्टेशनों और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों दोनों जगह असामान्य रूप से उच्च तापमान का लगातार बने रहना वर्तमान स्थिति को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाता है। यह गर्मी ऐसे समय में आई है जब कश्मीर में तापमान में आमतौर पर शरद ऋतु के आगे बढ़ने के साथ लगातार गिरावट आने की उम्मीद होती है, और घाटी में ठंडक का प्रकोप अधिक स्पष्ट होने लगता है।

अक्टूबर के लिए असाधारण बताया है। वे कहते थे कि इस समय के हिसाब से तापमान असाधारण रूप से अधिक है, काजीगुंड और कोकरनाग में अक्टूबर के अपने–अपने रिकार्ड टूट गए हैं। ऐसे तापमान असामान्य हैं और कश्मीर में भीषण गर्मी का संकेत देते हैं।

दुर्गा पूजा से पहले फंड जारी करनेकीमांग

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तुणमूल कांग्रेस ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच को राख किया। उन्होंने कोर्ट द्वारा नियुक्त उस स्पेशल ऑफिसर के खिलाफ यह कदम उठाया है, जो उन्हें पार्टी के तीन बेंचों के आकाउंट्स को अप्रोेट करने की इजाजत नहीं दे रहा है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच के सामने दायर अपनी याचिका में ममता गुट ने स्पेशल जज सुब्रत तालुकदार पर आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा से पहले पेसे निकालने की इजाजत नहीं दी। याचिका में कहा गया कि इस वजह से गुट त्योहार के मौसम से पहले घर का किराया और ऑफिस के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा है।

कर्नाटक के बल्लारी में मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप भाजपा नेता और चुनाव अधिकारियों पर प्राथमिकी

बेंगलुरु, एजेंसी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बल्लारी सिटी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से 7,561 नाम हटाने की कोशिश करने के आरोप में भाजपा के बूथ लेवल एजेंट–1 (बीएलए–1), बल्लारी सिटी कॉर्पोरेशन के एक पार्षद और तीन अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला वार्ड नंबर 23, बूथ नंबर 94 के कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) गौतम की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें बल्लारी सिटी कॉर्पोरेशन के पार्षद और भाजपा बीएलए–1 श्रीनिवास मोटकर, असिस्टेंट कमिश्नर नंदीश, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) सुमलता और केस वर्कर शरणबसवा शामिल हैं। शिकायत के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया 29 जून को शुरू हुई थी और 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद वोटरों को नाम जुड़वाने के लिए दावे पेश करने और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। शिकायत करने वाले का आरोप है कि 21 सितंबर को मोटकर ने बल्लारी

सिटी कॉर्पोरेशन इलाके में 7,561 वोटरों के नामों की दोबारा जांच की मांग वाली एक अर्जी स्वीकार की। शिकायत में कहा गया है कि चुनाव अधिकारियों ने पहले इस अर्जी को खारिज कर दिया था और इस बारे में एक पावती भी जारी की थी। इसके बावजूद आरोप है कि मोटकर ने 22 सितंबर को नाम हटाने के लिए ‘फॉर्म–7’ के तहत आवेदन जमा किए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित चुनाव अधिकारियों ने आपत्तियों के बावजूद वोटरों की दोबारा जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और मोटकर के निर्देशों पर काम किया।

98.08 प्रतिशत वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से थे

शिकायत में एक मुख्य आरोप यह है कि इन एप्लीकेशन में शामिल 7,561 वोटरों में से लगभग 98.08 प्रतिशत वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से थे। शिकायत करने वाले का आरोप है कि ये एप्लीकेशन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के मकसद से जमा किए गए थे।

किसान हित में सहकारी ऋण व्यवस्था होगी सरल: डॉ. यादव

भोपाल/ खंडवा, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान हित में सहकारी ऋण व्यवस्था को सरल और किसान हितैषी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को खंडवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीमच के चोंग कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने नीमच के किसानों से सीधे संवाद कर कृषि गतिविधियों, योजनाओं और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच उन्नत खेती और कृषि व्यापार का प्रमुख केंद्र है। नीमच मंडी में कृषि उपज की आवक वर्ष 2023–24 की 53.46 लाख क्विंटल से बढ़कर 2025–26 में करीब 72 लाख क्विंटल हो गई। मंडी की आय भी बढ़कर करीब 34.5 करोड़ रुपए पहुंची। उन्होंने कहा कि जिले में 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती हो रही है। सिंचाई परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्यपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। गांधीसागर में चीता परियोजना से पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाएं बनने की बात भी कही।

वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग

के जरिए

नीमच के

किसानों से

संवाद

मोबाइल पर टोका तो भड़के तीमारदार, डॉक्टर-गार्ड से भिड़े; वार्ड में चले लात-घूसे

मरीजों के सामने जमकर मारपीट, बीच-बचाव करने आए लोग भी घायल; वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल

रीवा, एजेंसी। संजय गांधी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के बीच उस समय दहशत फैल गई, जब मोबाइल पर बात करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मरीज के तीमारदार, डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड के बीच जमकर लात–घूसे चले। वार्ड में काफी देर तक हंगामा होता रहा। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, वार्ड में मरीज का तीमारदार मोबाइल पर बात कर रहा था। डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड ने उसे मोबाइल पर बात करने से रोकने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक–दूसरे से भिड़ गए। मारपीट के दौरान

बीच–बचाव करने पहुंचे लोगों को भी चोटें आईं। अचानक हुए हंगामे से वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन सहम गए। अस्पताल परिसर में अफरा–तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर भी घटना में शामिल लोगों की भूमिका जांची जा रही है।

बार-बार विवाद, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों, सुरक्षा गार्डों और मरीजों के तीमारदारों के बीच विवाद की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। ताजा मारपीट ने अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में मरीजों के सामने हिंसा होना व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करता है।

बीएलसी घटक में सबसे अधिक पक्के आवास पूरे करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में मध्य प्रदेश देश में अत्वल

■ **वारासिवनी नगर**

पालिका भी सम्मानित

भोपाल, देशबन्धु। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में स्वीकृत आवासों की तुलना में सर्वाधिक पक्के आवास पूर्ण करने पर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी पुरस्कार –2026 से सम्मानित किया गया है। वहीं एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर पालिका परिषद वारासिवनी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

विश्व आवास दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने पुरस्कार



प्रदान किए। राज्य शासन की ओर से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे तथा योजना के राज्य मिशन संचालक शिशिर गेमावत ने पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी रहा है।

प्रदेश ने स्वीकृत आवासों में से सर्वाधिक संख्या में पक्के मकानों का निर्माण पूरा कराया है। इसी उपलब्धि के आधार पर वारासिवनी नगर पालिका परिषद को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों वंचित और जरूरतमंद शहरी परिवारों

का पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में योजना का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य मिशन संचालक शिशिर गेमावत के अनुसार, मध्य प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों के तहत अब तक 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 9 लाख से अधिक आवास बनाकर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने भूमिहीन पात्र परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे देने सहित कई नीतिगत सुधार किए हैं। इससे पात्र परिवार ग्रामांतर्गत आवास योजना के लाभ से वंचित नहीं हुए। इस उपलब्धि में राज्य मिशन टीम, जिला प्रशासन, नगरीय निकायों और हितग्राहियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सार-समाचार

रानी दुर्गावती जयंती पर ‘धन्य धन्य बुंदेल धरा’ का मंचन

भोपाल, देशबन्धु। बुंदेलखंड की वीरंगना रानी दुर्गावती की जयंती पर सोमवार को हिंदी भवन में ‘ धन्य धन्य बुंदेल धरा’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महापौर मालती राय के मुख्य आतिथ्य एवं करुणाधाम आश्रम के सुदेश शांडिल्य महाराज के सानिध्य में हुआ। महापौर और अतिथियों ने रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आयोजकों ने महापौर मालती राय का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लेखक, साहित्यकार, आयोजन समिति के सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

घाटों को स्वच्छ रखने में नागरिक भी निभाएं जिम्मेदारी : महापौर

भोपाल, देशबन्धु। महापौर मालती राय ने सोमवार को शीतलदास की बगिया एवं गिज़ौरी घाट का निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने शोध कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने नागरिकों से भी घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। गिज़ौरी घाट पर महापौर ने पेकिंग ब्त्लॉक और कांक्र्रीटीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पीपल सहित अन्य पेड़ों की गुड़ाई और पर्याप्त साफ-सफाई करने, अव्यवस्थित पथर हटाने तथा खराब चेंबर का ढक्कन बदलने के निर्देश दिए। घाट को आकर्षक बनाने के लिए महरून, टेराकोटा और सफेद रंग से डिजाइन कराने को भी कहा। घाट पर कराए गए मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए स्थानीय रहवासीयों ने महापौर मालती राय का फूल मालाओं से सम्मान कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जौन अध्यक्ष आरती अनेजा, मुख्य अभियंता संतोष गुप्ता, नगर निगम के अधिकारी, मंदिर समिति के पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद थे।

साढ़े 3 हजार से अधिक विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां, 21 को स्वर्ण पदक

सीहोर, देशबन्धु। वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय का 7वां वार्षिक दीक्षांत समारोह शनिवार को उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। समारोह में विभिन्न शैक्षणिक संकायों के 3571 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 3062 बीटेक, 72 एमटेक, 156 एकीकृत एमटेक, 30 एमबीए, 142 एमसीए, 48 बीबीए, 3 बीआर्क, 12 बीएससी, 8 एमएससी और 38 पीएचडी विद्यार्थी शामिल रहे। समारोह में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के आर्किटेक्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि तथा इन-स्पेस के प्रमोशनल डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। विभिन्न पाठ्यक्रमों के 21 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय की स्टारस योजना के तहत 31 ग्रामीण विद्यार्थियों को भी डिग्रियां मिलीं। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के चयनित जिला टॉपर्स को शिक्षा, आवास और भोजन सहित निःशुल्क तकनीकी उच्च शिक्षा दी जाती है।

एलएनसीटी में संविधान कानून पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन



भोपाल, देशबन्धु। एलएनसीटी विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन विभाग द्वारा संविधान कानून के विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित न्यायविदों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और विधि विशेषज्ञों ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र में श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के

न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एच एम नवाज मुख्य अतिथि रहे। चांसलर जे एन चौकसे, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन कुम्हार, सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता अभिलेख संघ के अध्यक्ष देवव्रत लंदन, ब्रिटेन के बैरिस्टर रुपर्ट व्हीलर, कुलपति डॉ. नरेंद्र कुमार थापक और विधि संकाय के डीन डॉ. मुकेश साहू सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे।

तकनीकी सत्रों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत सहित संवैधानिक कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, गुरु कृष्णकुमार, मोहन कटारकी, जतिंदर चीम, अधिवक्ता सिद्धार्थ सिजोरिया सहित विशेषज्ञों ने विचार रखे। समापन पर चांसलर जे एन चौकसे ने सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित करने की घोषणा की।

स्टाफ बढ़ाने के लिए एक ही डॉक्टरों के नाम बार-बार दर्ज करने का आरोप आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े पर सृष्टि हॉस्पिटल संचालक पर प्राथमिकी

भोपाल, देशबन्धु। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के आरोप में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने करोंद स्थित सृष्टि हॉस्पिटल के संचालक राजकुमार सूर्यवंशी और अलग नाम करीब 15 ही थे। कई डॉक्टरों और अस्पताल पर योजना में शामिल होने के लिए डॉक्टरों और कर्मचारियों की फर्जी सूची देने तथा फर्जी हस्ताक्षर से जांच रिपोर्ट जारी करने के आरोप हैं।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक उपेंद्र जैन के हवाले से कहा गया कि जांच में सामने आया कि अस्पताल ने आयुष्मान योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर 45 डॉक्टरों और कर्मचारियों की प्रविष्टियां दर्ज की थीं, जबकि इनमें अलग-अलग नाम करीब 15 ही थे। कई डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों के नाम चार-चार बार दर्ज किए गए थे। सभी 45 प्रविष्टियों के सामने अस्पताल संचालक का मोबाइल नंबर दर्ज था।

जांच में एक महिला पैथोलॉजिस्ट का नाम भी चार बार दर्ज मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने अस्पताल में

पैसों के लेनदेन के कथित ऑडियो भी सामने आए, विद्यार्थियों ने लगाए प्रताड़ना के गंभीर आरोप

भौतिकी की शिक्षिका के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, छड़ से मारने और घर का काम कराने का आरोप

भोपाल, देशबन्धु। मिसरोद स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी सोमवार को फिजिक्स शिक्षिका के खिलाफ सड़क पर उतर आए। विद्यार्थियों ने शिक्षिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उन पर प्रताड़ित करने, लोहे की रॉड से मारने, घर का काम कराने तथा परीक्षा के प्रश्नपत्र जांचने के नाम पर पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षिका के व्यवहार को लेकर प्राचार्य से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षिका के खिलाफ %तानाशाही नहीं चलेगी% जैसे नारे लगाए। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि बबीता कुशवाह मैडम उनसे पढ़ाई के अलावा स्कूल और घर के काम भी कराती हैं। उनका दावा है कि उनसे घर के कांच साफ कराने सहित अन्य काम करवाए जाते हैं। विद्यार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल का फर्नीचर उठाने जैसे काम भी उनसे कराए जाते हैं।

छड़ से मारने का आरोप: प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने शिक्षिका पर लोहे की छ? से मारने का आरोप भी लगाया। विद्यार्थियों का कहना है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं।

बाल विवाह पर अब और कसेगा शिकंजा, कार्यशाला आज

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिकारियों का राज्य स्तरीय शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आज आर.सी.बी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के स्वर्ण जयंती सभागार में एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, बाल विवाह के प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई तथा अन्य संबंधित कानूनों के साथ इसके जुड़ाव पर अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यशाला की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया करेंगी। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सामान्य प्रशासन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी और अधिसूचित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी शामिल होंगे। भारती अली, बाल अधिकार विशेषज्ञ, नई दिल्ली बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सहित बाल विवाह



उन्होंने मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई को मांग की है।

पेपर बिगड़ने पर पैसे देने की बात का कथित ऑडियो: मामले में कुछ ऑडियो भी सामने आए हैं, जिनमें विद्यार्थियों ने मॉडिया को उपलब्ध कराया है। विद्यार्थियों का दावा है कि ऑडियो में भौतिकी विषय की शिक्षिका बबीता कुशवाहा की आवाज है। कथित ऑडियो में परीक्षा के पेपर से जुड़े मामले को ठीक कराने के लिए पैसों की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है।

विद्यार्थियों के अनुसार ऑडियो में कथित रूप से कहा गया है कि पेपर बिगड़ गया है तो उसे ठीक करने के लिए 200 रुपए से काम नहीं

चलेगा और कम से कम 1 हजार रुपए से अधिक देने पर मामला ठीक हो सकता है। एक अन्य कथित बातचीत में स्कूल में बैठने की अनुमति प्राचार्य से दिलाने की बात कही गई है और इसके लिए भी पैसे लगने की बात कही गई है। ऑडियो में कथित रूप से प्राइवेट फॉर्म भर कर विद्यालय में बैठने की व्यवस्था के लिए

पैसे लगने की बात सुनाई देने का दावा विद्यार्थियों ने किया है।

पेपर में पैसे नहीं देने पर फेल करने का आरोप विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के प्रश्नपत्र जांचने के दौरान भी पैसे मांगे जाते हैं। उनका दावा है कि पैसे नहीं देने पर फेल करने की धमकी दी जाती है। विद्यार्थियों ने इन आरोपों की जांच कराने और परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है।

प्राचार्य से नहीं हो सकी बात: मामले को लेकर स्कूल की प्राचार्य संध्या त्रिपाठी से मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। विद्यार्थियों ने बताया कि संबंधित शिक्षिका बबीता कुशवाहा

विद्यार्थियों की रचनात्मकता से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री

भोपाल, देशबन्धु। सेवा संकल्प अभियान के तहत 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, भोपाल में विद्यार्थियों की चित्रकला प्रदर्शनी एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रस्तुतियों का अवलोकन करेंगे और उनसे संवाद कर उनकी प्रतिभा तथा रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व, रचनात्मकता और जनभागीदारी से जोड़ने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में विद्यार्थी चित्रों के माध्यम से विकसित और सशक्त भारत की अपनी कल्पना प्रस्तुत करेंगे। वहीं भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण और सेवा भावना में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखेंगे।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों की विशेषज्ञों ने की सराहना

स्वच्छ हवा के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बने कार्ययोजना

भोपाल, देशबन्धु। स्वच्छ हवा के लिए बनाई जाने वाली कार्ययोजना शहर की स्थानीय परिस्थितियों और जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए। शहरी पर्यावरण प्रबंधन और स्वच्छ वायु के लिए भोपाल नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। यह बात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कही।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता मजबूत करने के विषय पर आयोजित प्रशिक्षण का शुभारंभ नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने कहा कि प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने से पहले जमीनी स्थिति को समझना और वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की सही व्याख्या करना जरूरी है। स्वच्छ हवा के उपाय हर शहर के आकार और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए।

उन्होंने भोपाल में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों तथा सड़कों के किनारे किए गए पक्कीकरण जैसे उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख प्रदूषण स्रोतों के आधार पर शहर स्तर पर कार्रवाई का आकलन करने में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण

अदालत के फैसले तक, न्याय प्रक्रिया को समझने का मौका

भोपाल, देशबन्धु। भारतीय न्याय व्यवस्था और नई न्याय संहिताओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेल दशहरा मैदान में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें अपराध की सूचना मिलने से लेकर पुलिस जांच, साक्ष्य जुटाने, फॉरेंसिक परीक्षण और न्यायालय के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को 14 अलग-अलग जोन में समझाया जा रहा है। पांच दिवसीय यह प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक चलेगी। इसका शुभारंभ 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था। प्रदर्शनी में मॉडल, वीडियो, चार्ट, डिजिटल तकनीक और सजीव प्रस्तुतियों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। यहां डायल-112, पुलिस की त्वरित कार्रवाई ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर और फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। डीएनए, अंगुलियों के निशान, हथियारों से जुड़े साक्ष्य और डिजिटल जांच के बारे में भी बताया जा रहा है। साइबर सुरक्षा वाले हिस्से में ऑनलाइन उगी से बचने के उपाय समझाए जा रहे हैं।

2 दिन की छुट्टी लेकर स्कूल नहीं आई हैं। हालांकि इस बात की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

विद्यार्थियों के अनुसार उन्होंने शिक्षिका के व्यवहार और कथित पैसों के लेनदेन को लेकर प्राचार्य से कई बार शिकायत की थी। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाया।

संयुक्त संचालक को भी दी जानकारी: विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक धर्मेन्द्र शर्मा को भी दिए जाने की बात सामने आई है। विद्यार्थियों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अब तक उन्हें कोई समाधान नहीं मिला है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से मामले में जांच या कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

पूरे मामले में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए आरोप, सामने आए कथित ऑडियो, शिक्षिका का पक्ष और स्कूल प्रबंधन की भूमिका जांच का विषय है। ऑडियो की तकनीकी जांच, विद्यार्थियों के बयान, पूर्व शिकायतों और स्कूल के अभिलेखों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

अमरावत खुर्द में विद्यार्थियों को वितरित किए स्कूली बैग

शिक्षा से होगी तरक्की, मिलेगी सफलता: गौर

भोपाल, देशबन्धु।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने सोमवार को शासकीय माध्यमिक एकीकृत शाला, अमरावत खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूली बैग वितरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में सर्वांगीण विकास और प्रगति का मूल आधार है।

जो विद्यार्थी निष्ठा एवं लगन से विद्या अध्ययन करता है, वह तरक्की और सफलता के नए शिखरों को स्पर्श करेगा है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय अवश्य भेजें, शिक्षित एवं गुणी बाल-पीढ़ी ही अपने परिवार के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के साथ समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में महती भूमिका निभाती है।

गौर ने उपस्थित विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद स्थापित कर उन्हें लगनपूर्वक अध्ययन करने तथा जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गुरुजनों का सम्मान करने



वाले तथा अनुशासित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। राज्यमंत्री गौर ने विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर विद्यालय के संचालन की समयबद्धता, पठन-पाठन का स्तर और भोजन की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर राज्यमंत्री ने शिक्षक वर्ग से संवाद करते हुए कहा कि शिक्षकों का पावन कर्तव्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करना है।

जनसंख्या गणना के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

जनगणना-2027 के दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू

भोपाल, देशबन्धु। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना के लिए जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को नगर पालिक निगम मुख्यालय अटल भवन में शुरू हुआ। प्रशिक्षण के पहले दिन जोनल अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, जनगणना लिपिकों और तकनीकी सहायकों को जनसंख्या गणना की प्रक्रिया और निर्धारित मानकों को जानकारी दी गई।

जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार जनसंख्या गणना को सुचारु रूप से कराने के लिए एकधिकृत प्रशिक्षक वंदना तिवारी और मनोज सैनी ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने गणना कार्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं और अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह सा? 9 बजे से शाम 6 बजे तक चला।



इसमें नगर निगम के उपायुक्त एवं नगर जनगणना अधिकारी होरेन्द्र सिंह कुशवाहा, संयुक्त निदेशक जनगणना निदेशालय नमित यादव सहित चार्ज कर्मांक 1 से 21 तक के जोनल और चार्ज अधिकारी, जनगणना लिपिक तथा तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनसंख्या गणना

कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देकर गणना कार्य को व्यवस्थित और सुचारु रूप से संपन्न कराना है। दो दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन भी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी।



भोपाल, मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

संस्थापक-संपादक : स्‍व. माधाराम सुरजन

मताधिकार पर जस्टिस भुईयां की अहम टिप्पणी

ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए देश में तेज हो रहे आंदोलन, चुनाव चोरी के मसले पर मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ बढ़ते संदेह के बीच एक राहत देने वाला बयान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुईयां की तरफ से आया है। हालांकि जस्टिस भुईयां ने यह टिप्पणी किसी सुनवाई के दौरान नहीं की है, न ही यह किसी फैसले का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश होने के नाते ही उनकी यह टिप्पणी काफी अहम है, क्योंकि इसमें नागरिकता और मताधिकार के बीच एक अटूट संबंध को रेखांकित किया गया है। एसआईआर पर विवाद इसी वजह से भी उठे हैं कि मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर दस-बीस नहीं कम से कम 13 करोड़ लोगों से मताधिकार छीन लिया गया है। मताधिकार छीनने की कवायद को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार के समान बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रक्रिया लाखों भारतीय नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर उन्हें अपने ही देश में बिना वोट वाले नागरिकों में बदल देती है, तो ऐसी प्रक्रिया 'स्वाभाविक रूप से मनमानी' होगी और संविधान के मूल ढांचे पर चोट करेगी।

हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित 19वें जस्टिस बोध राज साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन पर जस्टिस भुईयां ने कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों की दो श्रेणियां नहीं बनाता- एक वे जिनके पास वोट देने का अधिकार है और दूसरी वे जिनके पास यह अधिकार नहीं है। वोट छीनने वाली किसी भी प्रक्रिया को स्वभावतः मनमाना बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे किसी भी तरह की दलील या बहाने से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति संविधान के ‘दिल’ पर चोट करती है और भारत द्वारा अपनाए गए संवैधानिक शासन-व्यवस्था की ही नकार बन जाती है। जस्टिस भुईयां ने अपने भाषण में सीधे तौर पर न एसआईआर का नाम लिया, न ज्ञानेश कुमार का जिक्र इस संदर्भ में किया, न ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को जायज ठहराने वाले जो फैसले पिछले कुछ वक्त में आए हैं, उन पर कुछ खडा, लेकिन यह सब सीधे तौर पर न कहते हुए भी जस्टिस भुईयां ने अपने भाषण में दो टूक कहा कि किसी भारतीय नागरिक की पहचान से उसके वोट देने या मतदाता सूची में शामिल होने के अधिकार को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसकी तुलना शरीर से आत्मा निकालने से की। यानी नागरिकता और मताधिकार को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कानून के विद्यार्थियों और भावी वकीलों के जरिए देश को याद दिलाया कि भारत जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक के लिए सरकार के संचालन में भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण और सीधा माध्यम उसका वोट है। उन्होंने कहा कि मताधिकार नागरिकता का सार है और यही वह माध्यम है जिसके जरिए देश का सामान्य नागरिक शासन-व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। जस्टिस भुईयां ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने की संवैधानिक व्यवस्था करता है। जस्टिस भुईयां ने साफ कहा कि अनुच्छेद 326 के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई प्राधिकरण ऐसा नहीं कर सकता और कोई अदालत भी ऐसी प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दे सकती जो संवैधानिक मताधिकार को बड़े पैमाने पर खत्म करती हो। उन्होंने कहा कि 'कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है।'

इसके साथ ही जस्टिस भुईयां ने अनुच्छेद 326 को संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत से भी जोड़ा। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। जस्टिस भुईयां के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इस समानता को वास्तविक लोकतांत्रिक अर्थ देता है। यानी समाज में ऊंची स्थिति वाला व्यक्ति और सबसे निचले सामाजिक-आर्थिक पायदान पर खड़ा व्यक्ति दोनों की नागरिक के तौर पर एक जैसी हैसियत है और दोनों के चुनाव में एक-एक वोट है। उन्होंने इसे शारीर संविधान के उस पर्यवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के बावजूद राजनीतिक समानता सुनिश्चित की गई है। जस्टिस भुइयां ने अनुच्छेद 325 का भी उल्लेख किया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान है। जस्टिस भुईयां ने बाबा साहेब अंबेडकर के उद्देश्य को याद दिलाया कि संविधान निर्माताओं ने मताधिकार को केवल संसद द्वारा बनाए जाने वाले सामान्य कानून के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि इसे संविधान में ही जगह दी।

इसके साथ ही जस्टिस भुईयां ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी मतदाता का नाम एक बार मतदाता सूची में दर्ज हो जाने के बाद, मृत मतदाता के मामले को छोड़कर, उसे बिना नोटिस और सुनवाई के हटाना नहीं जा सकता। यह टिप्पणी एसआईआर के संदर्भ में खास महत्व रखती है। एक अकादमिक कार्यक्रम में जस्टिस भुईयां के संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित भाषण का महत्व एसआईआर तत्काल बंद करने की मांग के बीच और बढ़ जाता है। नेन्द्रे मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के कारण देश में लोकतंत्र कुचलने का जो निराशाजनक माहौल बनाया गया है, उसमें इन दिनों चल रहा आंदोलन और इसके साथ जस्टिस भुईयां का भाषण वैसा ही है जैसा फेज़ अहमद फेज़ ने कहा था कि-बीमार को बेवक़्फ़ करार आ जाए।

पितृसत्ता से लेकर जाति का विनाश, इतिहास के गैर-ब्राह्मणीकरण से मनु का श्राप तक"—पहली गैर में शेषक यह किसी को भी सामाजिक सुधार और जागरण की कार्यसूची लग सकती है। जाहिर है कि फुले दम्पति, पेरियार, डॉ अम्बेडकर तथा अन्य तमाम समाज सुधारकों की नहीं, अपने जरा अलग तरीके से गांधी की तथा उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यसूची का भी यह सब जरूरी हिस्सा रहा था। इसीलिए तो, इस राष्ट्रीय आंदोलन के गर्भ से जिस स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, उसका संविधान कम से कम इस कार्यसूची के अनुरूप जरूर था। इससे स्वाभाविक अपेक्षा तो यही की जाती है कि देश की शिक्षा व्यवस्था और खासतौर पर उच्च शिक्षा व्यवस्था इस सामाजिक कार्यसूची को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। हैरानी नहीं होगी कि इनके पांवों तले कुचले जाते रहे तबकों के बीच से तथा उनके हमदर्दों की कुछ गर्म आवाजें पितृसत्ता, जाति व्यवस्था, इतिहास के ब्राह्मणीकरण और मनुवाद को 'जहर' बताएं और इसकी काट या एंटी-डोट की तलाश को अपनी विद्वता का लक्ष्य बनाएं। यह सामाजिक क्रांति का वह एजेंडा है, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन पूरा तो नहीं कर सका, पर उसने बलपूर्वक देश के सामने रखा ही नहीं था, ऐसी शक्तियों को भी उन्मुक्त कर दिया था, जो इस एजेंडा को आगे ले जाने वाली थीं।

लेकिन, इसके उलट की क्या कहेंगे?पितृसत्ता के विरोध को, जाति के विनाश की वकालत को, इतिहास के ब्राह्मणीकरण की तथा मनु की आलोचना को ही अगर कोई 'जहर' बताए तो? स्वाभाविक रूप से इसका एक ही जवाब हो सकता है—यह तो सामाजिक प्रतिक्रांति का एजेंडा है। नेंद्र मोदी के नेतृत्व में संघ-भाजपा की सरकार के दबे-छुपे ढंग से सामाजिक प्रतिक्रांति की शक्तियों तथा प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने और उससे ज़्यादा खुलेआम सामाजिक क्रांति की प्रवृत्तियों को कमजोर करने को बात तो किसी से छुपी हुई नहीं थी। लेकिन, ऐसा लगता है कि मोदी राज के तीसरे कार्यकाल में सामाजिक प्रतिक्रांति की ताकतों के हाथों में बढ़ते पैमाने शासकीय नीति की बागडोर ही सौंपी जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वामपंथी के साथ-साथ अंबेडकरवादी विद्वता/विचारों की मौजूदगी को जांच की सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से सितंबर के आखिर में आयोग मांग, इसी सच्चाई को गाढ़े रंग से रेखांकित करती है।

इस प्रसंग को चूंकि मुख्त्यभार के मीडिया में बहुत हद तक अमदेद्वारे की बात दिया गया है, जबकि इस मामले में इसी प्रधानमंत्री कार्यालय की हैरान करने वाली सक्रियता स्पष्ट रूप

बच्चों के पोषण में डिजिटलीकरण न बने बाधा

हल के वर्षों में लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लक्षित समूहों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में भी तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इससे योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता बेहतर हो सकती है, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पात्र व्यक्ति योजना से वंचित रह जाए, तो यह चिंता का विषय है। बच्चों के भोजन और पोषण से जुड़ी योजनाओं में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश में बाल कुपोषण अब भी गंभीर समस्या बना हुआ है। ऐसे में आधार, ई-केवाईसी, फेम रिफर्किंगशन या किसी ऐप की तकनीकी प्रक्रिया के कारण किसी बच्चे का भोजन और पोषण नहीं रुकना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल योजनाओं को बेहतर बनाने और उनकी निगरानी के लिए हो सकता है, लेकिन गरीब, प्रवासी, आदिवासी और दूसरे वंचित परिवारों के बच्चों के लिए ऐसी शर्तें भोजन और पोषण सेवाओं तक पहुंच को और कठिन बना सकती हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार देश में पांच साल से कम उम्र के 29.3 प्रतिशत बच्चे डिगनेपन के शिकार हैं, 19 प्रतिशत बच्चे दुबले हैं और 31.8 प्रतिशत बच्चों का वजन उन की उम्र के अनुसार कम है। पिछले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुकाबले इन संकेतकों में सुधार दर्ज हुआ है, लेकिन करीब हर तीन में से एक बच्चे का उम्र के अनुसार कम वजन होना बताता है कि चुनौती अभी भी बड़ी है। बच्चे के जीवन के शुरुआती दो वर्षों में पर्याप्त और विविध आहार मिलना भी पोषण का महत्वपूर्ण आधार है इसलिए कुपोषण को खत्म करने के लिए बहुआयामी प्रयास जरूरी हैं।

बच्चे के पोषण की बुनियाद गर्भावस्था के दौरान ही पड़ जाती है। गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिलना, जन्म के बाद स्तनपान, छह महीने के बाद पर्याप्त और विविध पूरक आहार, साफ पानी, संक्रमण से बचाव और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना बच्चे के विकास से सीधे जुड़े हैं। इसके बाद आंगनवाड़ी और स्कूल में मिलने वाला भोजन आता है। इसलिए कुपोषण सामने आने के बाद बच्चे का वजन बढ़ाने के प्रयासों के साथ उन कारणों पर भी काम करना जरूरी है, जिनके चलते बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। इस पूरी व्यवस्था में आंगनवाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है। गरीब, आदिवासी, दूरदराज और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी पोषण के साथ स्वास्थ्य और शुरुआती देखभाल की व्यवस्था भी है। इसके लिए जरूरत के मुताबिक पर्याप्त आंगनवाड़ी केंद्र, अच्छे भवन, पानी, बिजली और स्वच्छता की सुविधाएं तथा पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता जरूरी हैं। भोजन की गुणवत्ता पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध दाल, मोटे अनाज, सब्जियां और दूसरी पौष्टिक सामग्री से गर्म पका भोजन दिया जा सकता है। स्कूलों में स्थानीय भोजन और किचन गार्डन को बढ़ावा देने के साथ बच्चों में जंक फूड के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के उपाय भी जरूरी हैं।

मां के पोषण और उसकी सामाजिक सुरक्षा का सवाल भी इससे जुड़ा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिलने का असर मां और बच्चे दोनों के पोषण पर पड़ता है। मातृत्व लाभ की पहुंच बढ़ाने के साथ तीन साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच और शुरुआती देखभाल की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। प्रवासी मजदूरों, बेघर और विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए समस्या और

से देखने को मिलती है, जो पूरे शासन के इस दिशा में प्रवृत्त होने का संकेत देती है, इसलिए हम यहां इस प्रसंग का थोड़े विस्तार से जिक्र करना चाहेंगे। इस प्रकरण की शुरुआत, 26 सितंबर को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए एक गुमनाम ट्वीट से होती है। इस ट्वीट में देश के वर्तमान नीति निर्धारकों को चेताया जाता है कि पितृसत्ता, जाति, ब्राह्मणवाद, मनुवाद की आलोचनाओं का 'जहर' युवा दिमागों में भरा जा रहा है, जिसके जरिए वामपंथी जुड़ेली शिक्षण का उपयोग अपनी कतारों में भरती के लिए रंगरूट तैयार करने के लिए कर रही है।

बहरहाल, वामपंथ पर हमले की आड़ में वास्तव में सामाजिक रूप से उत्पीड़ितों, खासतौर पर वंचित जातियों



तथा महिलाओं के अधिकारों तथा उनकी समानता की पुकारों का रास्ता खोलने वाली और उनका रास्ता रोकने वाली पंथाओं को उच्च शिक्षा के दायरे से बहिष्कृत ही करने की आरएसएस की मांग तब पूरी तरह से उजागर हो जाती है, जब उक्त ट्वीट के साथ लगायी गयी सूची में डॉ. अंबेडकर की 'एन्टिलेशन ऑफ कास्ट' से लेकर, पेरियार, फुले दम्पति तक के लेखन को उक्त 'जहर' के उदाहरण के रूप में गिनाया जाता है। ट्वीट के साथ जोड़ी गयी तस्वीर में पूरी 35 पुस्तकें हैं, जिनमें आसानी से समझ में आने वाले कारणों से, महिला लेखिकाओं की संख्या अनुपातहीन तरीके से ज़्यादा है। यानी यह वामपंथ का नाम लेकर, हर प्रकार की प्रगतिशील धाराओं और खासतौर पर जातिभेद-विरोधी तथा लिंगभेद-निषेधक बराबरी के विचारों को शिक्षा के दायरे से उसी तरह बहिष्कृत करने के प्रयासों का एक उदाहरण है, जिस तरह के हमलों के जरिए ब्राह्मणवाद ने बहुत पुराने जमाने में चार्वाक और आजीवक जैसी भौतिकवादी दार्शनिक धाराओं को हाशिए से भी नीचे

■ राजु कुमार

कठिन है। पहचान या स्थायी पते के अभाव में यदि कोई बच्चा आगनवाड़ी, स्कूल, भोजन या स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर रह जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर पहले से वंचित परिवारों

पर पड़ता है। बच्चों के भोजन की व्यवस्था में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, रसोइयों, किसानों, ग्राम पंचायतों, माता-पिता और स्कूल प्रबंधन समितियों को इससे जोड़ने पर भोजन की गुणवत्ता और निगरानी दोनों में मदद मिल सकती है। स्थानीय किसानों से दाल, मोटे अनाज और दूसरी पौष्टिक सामग्री की खरीद बच्चों को स्थानीय और विविध भोजन उपलब्ध कराने के साथ किसानों और स्थानीय आजीविका को भी सहारा दे सकती है। इसके साथ सामाजिक अंकेक्षण, भोजन की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच, सरकारी ठेकों में पारदर्शिता और शिकायतों के निवारण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के भोजन और पोषण की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए निजीकरण के बजाय सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे हुए

स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है। बदलती जलवायु और बा-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का असर परिवारों की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या आजीविका का नुकसान अंततः घर में उपलब्ध भोजन को प्रभावित करता

है। इसलिए आपदा के समय बच्चों और गर्भवती महिलाओं के भोजन और पोषण की व्यवस्था को राहत कार्यक्रमों का जरूरी हिस्सा बनाना होगा। स्थानीय कृषि और पोषण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। आंगनवाड़ी, आशा और पीएम पोषण से जुड़े फ्रंटलाइन कार्यक्रमताओं को पर्याप्त मानदेय, सामाजिक सुरक्षा, जरूरी संसाधन और काम की बेहतर परिस्थितियां दिए बिना जमीनी स्तर पर पोषण सेवाओं में अपेक्षित सुधार मुश्किल है।

भोजन और पोषण से जुड़ी योजनाओं में बढ़ते डिजिटलीकरण को भी इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है, ताकि तकनीक बच्चों तक भोजन और पोषण की पहुंच में बाधा न बने। डिजिटलीकरण के कारण बच्चे की भोजन और पोषण सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बच्चों के निजी आंकड़ों की सुरक्षा का सवाल भी इससे जुड़ा है। दूसरी ओर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों पर डिजिटल रिपोर्टिंग का काम इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि बच्चों के साथ सीधे काम करने का उनका समय कम होने लगे। तकनीक सुविधा और निगरानी का साधन रहे, अधिकार पाने की शर्त नहीं।

भोपाल में हाल में हुए बच्चों के भोजन के अधिकार पर तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में तीन दिनों की चर्चा के बाद जारी पोषण में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। अधिवेशन में प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यूां द्रेज सहित भोजन के अधिकार के लिए लंबे समय से काम कर रहे कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अधिवेशन में भी इस बात पर जोर दिया गया कि कुपोषण रोकने के प्रयास बच्चे के कुपोषित पाए जाने के बाद ही शुरू नहीं होने चाहिए। मां के पोषण से लेकर बच्चे के शुरुआती आहार, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूल तक पोषण की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रेच और शुरुआती देखभाल जैसी गंभीरा समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व सुरक्षा, स्थानीय खाद्य व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार, पहचान या कोई तकनीकी प्रक्रिया किसी बच्चे और उसके भोजन और पोषण के अधिकार के बीच न आए।

आपके पत्र

कैप्टन स्मित ने संकट की घड़ी में दिताया अदम्य साहस

विमान में बैठे यात्रियों के लिए उड़ान का समय सामान्यतः रोमांच और सुविधा का अनुभव होता है, लेकिन जब हजारों फीट की ऊंचाई पर अचानक कोई गंभीर संकट सामने आ जाए तो कुछ ही क्षणों में पूरी स्थिति जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष में बदल सकती है। ऐसे समय में विमान के पायलट की भूमिका केवल विमान उड़ाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी सूझबूझ, धैर्य, निर्णय क्षमता और साहस सैकड़ों लोगों के जीवन की रक्षा का आधार बन जाते हैं। हाल की एक घटना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि संकट के सामने मजबूत हौसला और पेशेवर जिम्मेदारी कितनी बड़ी ताकत बन सकती है।

दुबई से इजरायल जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में सामने आए गंभीर खरबे के दौरान कैप्टन स्मित मच्छर ने जिस तरह परिस्थितियों का सामना किया, उससे उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विमान के भीतर अचानक पैदा हुए संकट ने यात्रियों और चालक दल के सामने असाधारण चुनौती

एक विमानन संबंधी कार्यक्रम में भाग

धकेल दिया था।

इस गुमनाम ट्वीट के आने के बाद जो कुछ होता है, वह और भी ज़्यादा मामूखेज है। प्रधानमंत्री कार्यालय इस ट्वीट का स्वतः संज्ञान लेकर, उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखता है और संबंधित विभाग उसी दिन, यानी 27 सितंबर को ही सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिखकर उनसे फौरन इन शिकायतों पर उनका जवाब मांगता है। जाहिर है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय तुरंत इस मामले की समीक्षा में जुट जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों से इस शिकायत के सिलसिले में पूछा गया एक सवाल और भी ज़्यादा आश्चर्याएं पैदा करने वाला है। उन्हें यह भी बताना है कि उक्त 'जहर' फैलाने वाले विचारकों/लेखकों से जुड़े पाठ्यक्रमों में कितने

राष्ट्रीय आंदोलन से उन्मुक्त हुई सामाजिक क्रांति को पलटने के लिए संघ-भाजपा का प्रतिक्रांतिकारी हमला दो टांगों पर खड़ा है—हिंदू श्रेष्ठतावाद और मनुवाद या ब्राह्मणवाद, जिसमें सवर्णवाद और मर्दवाद दोनों का योग है। शासन के विभिन्न स्तरों तक इस हमले के पहुंचने से सामाजिक प्रतिक्रांति का वास्तविक खतरा पैदा हो गया है।

छात्र हैं। यानी कुल मिलाकर इस जहर के फैलने और फैलाने का पैमाना कितना है? इसके लिए कितनी और कैसी शेरबंदी की जरूरत होगी?

बेशक, जातिवाद तथा मर्दवाद के पक्ष में वर्तमान शासन के सीधे हस्तक्षेप का यह पहला उदाहरण हो भी, तब भी इसके पीछे चले आ रहे एक लगातार जारी सिलसिले को याद रखना जरूरी है।। पाठकों को याद होगा कि रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या समेत उच्च शिक्षा संस्थाओं में जातिवादी भेदभाव के अनेक प्रकरणों की पुष्टभूमि में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने आधे-अधूरे तरीके से जो दिशा-निर्देश तैयार किए थे, उनके खिलाफ भी जाहिर है कि संघ परिवार के संगठनों की सलिसता के साथ, विरोध का तुफान खड़ा करने की कोशिश की गयी थी। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सुनवाई कर, इन दिशानिर्देशों पर रोक ही लगा दी थी।

सवर्ण गोलबंदी के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए,

नीट परीक्षाओं की धांधली से भड़के छात्रों और युवाओं के जंतर-मंतर आंदोलन के बाद के दौर में, उसके समानांतर सवर्ण युवाओं की लामबंदी की कोशिशों के जरिए, युवाओं को बांटने की कोशिश की गयी थी। और जब यह कोशिश, खास कामयाब नहीं हुई, तब जंतर-मंतर आंदोलन के फौरन बाद, आरक्षण व्यवस्था में सुधार के नाम पर, आरक्षण-विरोधी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गयी। यह दूसरी बात है कि इसका ज़्यादा व्यापक प्रभाव नहीं नजर आया, उल्टे इसके पीछे सत्ताधारी भाजपा तथा संघ के नेताओं का हाथ होने का सच ही उजागर हो गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के उप-मुख्यमंत्री, बुजेश पाठक खासतौर पर इस सवर्ण युवाओं के पीछे खड़े उपा आ रहे थे और उनकी सरकार इसे छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही थी। इसी खुलमखुल्लापन को अब केंद्र की शिक्षा नीति में अमली मंजिल पर पहुंचा दिया गया है।

यह भी याद रहे कि संघ परिवार पहले से ही जातिवाद तथा लिंगभेद को सच्चाइयों को ही नकारने के जरिए, इन असमानताओं को मिटाने के संघर्षों को ही गैर-जरूरी साबित करने में लगा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसी प्रतिगामी रुख की शासकीय नीति के स्तर पर अभिव्यक्ति में, मोदी सरकार इसके लिए बराबर लड़ती आयी है कि रंगभेद-विरोधी वैश्विक एकजुटता में, भारत के जाति भेद के जिक्र को हर्गिज शामिल नहीं किया जाए। इसी प्रकार, पश्चिमी देशों में कुछ शैक्षणिक परिसरों में जहां भारतीय छात्रों की भी टीक-टाक उपस्थिति है, जब भी भेद-भाव विरोधी पहलों के हिस्से के तौर पर, जाति-भेद विरोधी कदमों के शामिल किए जाने की बात आयी है, संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने ही गैर-जरूरी साबित करने में हाथ रखने के जरिए वर्तमान सरकार ने भी, ऐसी सभी कोशिशों का विरोध ही किया है। यह आरएसएस के बुनियादी एजेंडा को ही दिखाता है, जो अपने सारे दिखावे के बावजूद, जातिवादी तथा लिंगभेदी, विशेषाधिकारों का हिमायती ही बना रहा है।

राष्ट्रीय आंदोलन से उन्मुक्त हुई सामाजिक क्रांति को पलटने के लिए संघ- भाजपा का प्रतिक्रांतिकारी हमला दो टांगों पर खड़ा है—हिंदू श्रेष्ठतावाद और मनुवाद या ब्राह्मणवाद, जिसमें सवर्णवाद और मर्दवाद दोनों का योग है। शासन के विभिन्न स्तरों तक इस हमले के पहुंचने से सामाजिक प्रतिक्रांति का वास्तविक खतरा पैदा हो गया है। जातिगत तथा लैंगिक समानता समेत, हर तरह की समानता की सोच आज निशाने पर है। कथित दिमागी नक्सलों के खिलाफ युद्ध को वर्तमान संघी सत्ता की पुकार, इसी सामाजिक प्रतिक्रांति का युद्धबोध है।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं ।)

ललित सुरजन की कलम से

लक्ष्यवेध पर संदेह क्यों?

‘एक टीकाकार ने लिखा है कि मोदी सरकार ने सड़किल स्ट्रीट के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला है। ऐसा कोई ऑपरेशन वास्तव में हुआ या नहीं इसे कुछ देर के लिए भूल जाएं। यदि भारत की जनता इस बात से प्रसन्न और आश्चस्त होती है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से बदला लेने में सक्षम है व हाथ पर हाथ धरे रहने की बजाय कार्यवाई कर रही है तो यही सही। कुछ अन्य टीकाकारों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि बीते वर्षों में अनेक बार ऐसे सीमित आक्रमण भारत करते रहा है, लेकिन पूर्व में इसका हिंदीौरा कभी नहीं पीटा गया। इस संदर्भ में पूर्व प्रसंगों के विवरण भी दिए गए हैं। कहने का आशय यह कि मोदी जो इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।’

‘हम मानते हैं कि अगर सचमुच यह लक्ष्यभेदी आक्रमण किया गया था और वर्तमान सरकार इससे लाभ उठा रही है तो यह एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। किन्तु इसमें अगर सिर्फ प्रचार पाने की चाहत है तो आगे चलकर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं है।’

(देशबन्धु में 06 अक्टूबर 2016 को प्रकाशित)
https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

पावन प्रसंग

पितृ तर्पण

भारतीय समाज में धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। धर्म का प्रयोग धार्मिक कृत्यों, रीति-रिवाजों, व्रत व त्योहारों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा व्यक्तिवत् विकास में सहायक माना जाता है। इस प्रकार धर्म व्यवस्था से व्यक्ति और समाज अतुष्टासित होता है। भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है। हमारे संस्कारों में मां के चरणों में ममता, त्याग और करुणा का संसार दिखाई देता है, तो पिता के जीवन में परिश्रम, जिम्मेदारी और सुरक्षा की छाया। मां-बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। वे अपनी जरूरतें कम कर बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। उनकी खुशियां बच्चों की मुस्कान में बसती हैं और उनका जीवन परिवार को संवराने में बीत जाता है।

पितृपक्ष; जिसका विशेष महत्व हिंदू धर्म में माना जाता है। पितृ पक्ष में पूर्वजों को विधि-विधान से तर्पण करना पितृ तर्पण कहलाता है। पितृ तर्पण आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों तक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज कुटुम्बजनों से मिलने स्वर्ग से धरती पर आते हैं व उन्हें आशीर्ष देते हैं और इसलिए तालाब में जाकर जल अर्पित किया जाता है।

पितृपक्ष में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। पितृपक्ष में कुछ कार्य निषिद्ध माने गए हैं; महिलाओं को नये वस्त्र, नया आभूषण, नई चूड़ी पहनना वर्जित होता है साथ ही गर्म पानी में कपड़े डुबाना, सूप छलनी बजाना, पटक कर कपड़े धोना आदि निषिद्ध होता है। व्यक्ति के मृत्यु के एक वर्ष पश्चात प्रथम बार पितृ तर्पण करने को पितर मिलाना कहा जाता है। सभी पुरुषों की तिथि के अनुसार पितृतर्पण किया जाता है तथा सभी महिलाओं का तर्पण नवमी तिथि के दिन किया जाता है जिसे मातृनवमी कहा जाता है।

पितृपक्ष के पहले दिन को पितरबैसका व अंतिम दिन को पितरखेदा कहा जाता है। पितृपक्ष के प्रथम दिन से पूरे 15 दिनों तक प्रातः चौर के आंगन में गोबर से चौकोर लीपकर चावल के आटे से चौक बनाकर फूल वह भोगी उड़द के दाल को छिड़क कर लोटे में पानी रखा जाता है। बड़ा व पूड़ी का भोग लगाकर भोग लगाया जाता है। बड़ा, पूरी व मालपुआ आदि का छोटा-छोटा टुकड़ा छप्पर में भी रखा जाता है ताकि कौवा व अन्य पक्षी पितर के रूप में आकर ग्रहण करें।

पितृपक्ष के 15 वें दिन पितृ अमावस्या के दिन को पितरखेदा कहा जाता है, इस दिन 15 दिनों का होम, बड़ा, बोबर व पूड़ी को पोटली में बांधकर उसमें पैसे डालकर तालाब में विसर्जित किया जाता है जिससे मछली आदि जीवों को भोजन मिलता है। ऐसा लोकविश्वास है कि-यह सामग्री पितरों को प्राप्त होता है। इस तरह ग्रामीण अंचल में विधि-विधान से पितरों का तर्पण किया जाता है।

डॉ. श्रीमती ज्योति किरण चंद्राकर

सार-समाचार

मौखिक नियमों से डरा-धमकाकर अपात्र कर रही सर्वे टीम - पार्षद



आग्रा, देशबन्धु। पार्षद श्रीमती तस्कनी शेख रईस ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं तहसीलदार रामलाल पगारे को आवेदन देकर मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के सर्वे में हो रही भारी अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। पार्षद ने बताया कि सर्वे टीम द्वारा गरीबों को मौखिक और फर्जी नियम बताकर डराया जा रहा है, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन में ऐसे कोई नियम हैं ही नहीं। पार्षद प्रतिनिधी शेख रईस ने मांग की कि लंबित नामांतरण फाइलें 7 दिन में दूढ़कर नामांतरण किया जाए या पैसा वापस किया जाए या रसीद पर ही पात्र किया जाए।, हर वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना का कैंप लगाया जाए, ढोल-सुनादी कराई जाए और फोन लगाकर बुलाया जाए। एक समग्र आईडी पर 2-3 भाई हैं और मकान का नामांतरण अलग-अलग है तो सभी को लाभ दिया जाए। यदि एक समग्र पर एक ही लाभ का कोई नया लिखित आदेश आया है तो उसकी कॉपी सभी 18 पार्षदों को दी जाए, मौखिक आदेश नहीं चलेगा। पार्षद प्रतिनिधि शेख रईस ने कहा कि यदि 7 दिन में सुधार नहीं हुआ तो गरीब हितग्राहियों के साथ नगर पालिका का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचित अभ्यर्थियों को प्रदान किए प्रमाण पत्र

रायसेन, देशबन्धु। त्रि-स्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन-2026 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक-3, बाड़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कन्हवार में सरपंच पद हेतु हुए निर्वाचन तथा मतों की गणना उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला पंचायत रायसेन के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-03 से निर्वाचित श्रीमती पूजा राकेश चौकसे, जिला पंचायत रायसेन के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-14 से निर्वाचित रायेश्वर पिता टीकाराम निवासी ग्राम भारकच्छबुर्दा तथा जिला पंचायत रायसेन के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-17 से निर्वाचित संजू पिता श्री राम निवासी वार्ड नं.-13 जावरा मलखार बगवानी को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी तथा संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रामपुरा खुर्द में स्वास्थ्य शिविर एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



सिलवानी, देशबन्धु। शासकीय महाविद्यालय सिलवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के गोद ग्राम रामपुरा खुर्द में विभिन्न जनसेवा एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता जागरूकता रैली एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 52 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण किया गया। सिविल अस्पताल से पहुंचे डॉ. इजहार खान, फार्मासिस्ट रोहित रघुवंशी, बद्री प्रसाद साहू एवं शुभम दीक्षित ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच काता यादव ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहें। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉ. लक्ष्मीकांत नेमा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महिला इकाई प्रभारी डॉ. अभिलाषा ठाकुर, राघवेंद्र सिंह राजपूत, डॉ. मुदुल सेन एवं डॉ. ओपी वर्मा सहित महाविद्यालय के बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं ग्रामीजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली।

अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को मिले पीएम आवास योजना का लाभ : कलेक्टर



रायसेन, देशबन्धु। कलेक्ट्रेट सभाक्षेत्र में आयोजित टीएल बैचक में कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा विभागावार सीएम हेल्पलाईन, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, सेवा संकल्प अभियान सहित शासन की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि गैरतगंज, गौहरगंज तथा सिलवानी में बेहतर कार्य हुआ है। अन्य तहसीलों में भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाई जाए। साथ ही समयसीमा से बाहर होने वाले प्रकरणों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने तहसीलवार स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन

योजना 2026 की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में सभी तहसीलों में बेहतर कार्य हुआ है। उन्होंने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 अंतर्गत रजिस्ट्री इनीशिएट कराने में उत्कृष्ट कार्य पर तहसीलदार सुल्तानपुर श्रीमति चंचल जैन, नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज श्री निलेश सरवटे, राजस्व निरीक्षक तहसील गौहरगंज सुश्री शुभा मरकाम, तक नौकी सहायक तहसील सुल्तानपुर श्रीमति वर्षा वाडिवा को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन कार्य में और अधिक मेहनत कर कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों वाहनों की आवाजाही, त्यस्त चौराहे पुलिस विहीन



सांची, देशबन्धु। ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने के कारण नगर में दिनभर हजारों छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। वाहनों की बढ़ती संख्या और तेज रफ्तार के बीच नगर के प्रमुख एवं व्यस्त चौराहों पर यातायात व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से लोगों को सड़क पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई व्यस्त चौराहे पुलिस एवं यातायात व्यवस्था के इंतजामों से महरूम बने हुए हैं।

जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के

कारण सांची में लगातार वाहनों का आवागमन बना रहता है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पार करना स्थानीय नागरिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। नगर की सड़कों से सटे क्षेत्रों में कई विद्यालय भी संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं का प्रतिदिन आना-जाना होता है। ऐसे में विद्यार्थियों को सड़क पार करते

समय हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय नागरिक भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। वहीं देश-विदेश से सांची पहुंचने वाले पर्यटकों को भी नगर के व्यस्त मार्गों और चौराहों से गुजरते समय सड़क पार करने में परेशानी उठानी पड़ती है। वाहनों की लगातार आवाजाही के बीच कई स्थानों पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके बावजूद नगर के प्रमुख चौराहों पर नियमित यातायात पुलिस की तैनाती दिखाई नहीं देती। विशेष एवं अति विशिष्ट लोगों के सांची आगमन के दौरान ही चौराहों पर यातायात पुलिस की मौजूदगी नजर आती है, जबकि सामान्य दिनों में यातायात व्यवस्था काफी हद तक स्थानीय स्तर पर ही निर्भर रहती है। बताया जाता है कि वर्षों पहले सांची में यातायात पुलिस की पदस्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। इसके बाद से नगर की यातायात व्यवस्था के लिए स्थायी रूप से यातायात पुलिस

पितृपक्ष में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखें : दीक्षित



सिलवानी, देशबन्धु। पितृपक्ष के अवसर पर कुशवाहा परिवार द्वारा नगर में स्टेट बैंक के पास स्थित मंगल भवन में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के द्वितीय दिवस श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहे। कथा व्यास पंडित बलराम दीक्षित ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कराते हुए पितृपक्ष के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कथा व्यास पंडित बलराम दीक्षित ने कहा कि पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा,

स्मरण और कृतज्ञता व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। सनातन परंपरा में पितरों का विशेष स्थान है। इस दौरान श्रद्धापूर्वक तर्पण, श्राद्ध एवं दान-पुण्य करने से पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों के संस्कारों और आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने श्रद्धालुओं को अवगत कराते हुए कहा कि भागवत कथा मनुष्य को सत्य, धर्म, सदाचार और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कथा के दौरान भजनों एवं धार्मिक प्रसंगों से वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागवत कथा का श्रवण किया। आयोजक परिवार ने श्रद्धालुओं से आगामी दिनों में होने वाली कथा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया।

मातृ-शिशु पोषण पर दिया जोर : महिलाओं से संवाद कर स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पोषण आहार के प्रति किया जागरूक



भैरून्दा, देशबन्धु। महिला एवं बाल विकास विभाग के सेवा, सेवा संस्कार अभियान के तहत नगर में तीन दिवसीय आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर के 15 वार्डों में संचालित 23 आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुए कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के परिजनों से संवाद कर मातृ-शिशु पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर, रमा शिशिर, एडवोकेट अलका चौहान, रचना भारी, अनीता लखेरा, रजनी

शर्मा सहित आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक रेखा दुबे मौजूद रहें। इस दौरान महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाने, नियमित वजन मापन कराने और पूरक पोषण आहार का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर ने कहा कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए परिवार और आंगनवाड़ी केंद्र के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से शासन की योजनाओं का लाभ लेने और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। एडवोकेट अलका चौहान ने महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र केवल पोषण आहार वितरण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और मातृ स्वास्थ्य को मजबूत करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र आते और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भागीदारी करने की अपील की। रमा शिशिर ने भी महिलाओं को बच्चों के पोषण और गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के परिजनों से देखभाल के संबंध में जानकारी दी। पर्यवेक्षक रेखा दुबे ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि गर्भावस्था से लेकर छह वर्ष तक के बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण गतिविधियां

भी आयोजित की गईं। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए आंगनवाड़ी सेवाओं और योजनाओं से मिले लाभ की

आष्टा के पांच आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हुआ आंगन मिलन सेवा अभियान

आग्रा, देशबन्धु। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर के वार्ड क्रमांक 12, 13, 16, 17 एवं 18 के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत केंद्रों पर आकर्षक पोषण मटका भी सजाया गया, जिसमें उपस्थित गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण आहार के महत्व को समझाया गया। कार्यक्रम में नपाध्यक्ष श्रीमती हेमकुंवर मेवाड़ा, नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंजनी चौरसिया, वार्ड पार्षद रवि शर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिकों को किसी न किसी योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। श्री मेवाड़ा ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए पात्र हितग्राहियों को दृढ़कर उन्हें लाभ दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, लाडली बहना योजना और पीएम आवास योजना सहित अन्य कल्याणकारी नीतियों की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। नन्हें-मुने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन आने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अतिथियों द्वारा उपहार का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंजनी चौरसिया, पार्षद रवि शर्मा, विशाल चौरसिया, मातृ संयोगिनी समिति की अध्यक्ष एडवोकेट अनिता यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्पना राठौर, सहायिका संजना बड़ौलिया सहित बड़ी संख्या में वार्ड की गर्भवती व धात्री महिलाएं और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

जानकारी दी। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, महिलाएं, बच्चे और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।



विद्यार्थी, स्थानीय नागरिक और पर्यटक रहते हैं दुर्घटना की आशंका में

राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों वाहनों की आवाजाही, त्यस्त चौराहे पुलिस विहीन

डिवाइडर और बिजली के खंभों पर प्रचार सामग्री से बिगड़ी शहर की सुंदरता

चौराहों पर दृश्यता प्रभावित, हदसे का खतरा

भैरून्दा, देशबन्धु। नगर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए बनाए गए डिवाइडर और सार्वजनिक स्थान इन दिनों प्रचार सामग्री से पटे नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड से लेकर ब्रह्मदेव की पुलिया और निम्न गांव रोड तक जगह-जगह बैनर, होर्डिंग और प्रचार सामग्री लगाई गई है। कुछ निजी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों के प्रचार के लिए डिवाइडर और बिजली के खंभों पर बोर्ड तक लगा दिए हैं। वहीं गरबा सहित निजी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए भी बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं।

रहवासियों का कहना है कि कई स्थानों पर लगाए गए बड़े होर्डिंग और बैनर के कारण चौराहों पर आने-जाने वाले वाहनों की दृश्यता प्रभावित हो रही है। वाहन चालकों को दूसरी दिशा से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खासकर भीड़भाड़ वाले मार्गों और चौराहों पर यह स्थिति अधिक परेशानी पैदा कर रही है। रहवासियों ने नगर परिषद से मांग की है कि सार्वजनिक डिवाइडर, बिजली के खंभों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर लगाई गई प्रचार सामग्री को तत्काल हटया जाए। उनका कहना है कि इससे शहर की सुंदरता भी बनी रहेगी और यातायात में हो रही परेशानी भी कम होगी।

निर्देश के बाद भी नहीं हटे : बताया गया कि नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर और सीएमओ राम प्रसाद भवरे द्वारा प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई स्थानों से बैनर और होर्डिंग नहीं हटाए गए। इससे नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

अब कार्रवाई की तैयारी : नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर ने बताया कि प्रचार सामग्री हटाने को लेकर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। संबंधित लोगों को नोटिस दिए जाएंगे और चालानी कार्रवाई के साथ डिवाइडर व बिजली के खंभों पर लगे होर्डिंग हटवाए जाएंगे।

की तैनाती नहीं हो सकी है।

नियमित तैनाती की जरूरत : स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस की नियमित तैनाती होने से

एक ओर जहां पैदल राहगीरों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को सड़क पार करने में सुविधा मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार वाहनों की गति पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा



सकेगा। ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगरी में बढ़ते यातायात को देखते हुए प्रमुख चौराहों पर नियमित सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विकासखंड स्तरीय मोगली बाल महोत्सव प्रतियोगिता संपन्न

सिलवानी, देशबन्धु। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) भोपाल के तत्वावधान में जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन निर्मल निरंजन तिवारी के मार्गदर्शन एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी रूपेंद्र ठाकुर के निर्देशन में सेठ अमरचंद समैया शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलवानी में विकासखंड स्तरीय मोगली बाल महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता का संयोजन विद्यालय के प्राचार्य एनपी शिल्पी द्वारा किया गया। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं निर्णायक समिति के नेतृत्व में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। प्रतियोगिता बाल महोत्सव विकासखंड मोगली प्रतियोगिता के नोडल प्रभारी शिक्षक मयंक रघुवंशी ने दी।



प्रतियोगिता में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

प्रतियोगिता के प्रथम चरण में विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ग से विद्यार्थियों का चयन क्रिज प्रतियोगिता के लिए किया गया। क्रिज में विद्यार्थियों ने वन्यजीव, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर उत्साहपूर्वक दिए और वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति अपने

संकल्प को व्यक्त किया। इस अवसर पर सांदीपनि विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

यह रहे विजेता : कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान अनामिका जाटव (पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिलवानी), द्वितीय स्थान कुष्णा ठाकुर (सांदीपनि माध्यमिक विद्यालय, सिलवानी) तथा तृतीय स्थान चांदनी आदिवासी (शासकीय सांदीपनि माध्यमिक शाला, सिलवानी) ने प्राप्त किया।

वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान यूपेशपुरी गोस्वामी (सांदीपनि विद्यालय, सिलवानी) ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान दुर्गा धाकड़ (सांदीपनि विद्यालय, सिलवानी) एवं मयंक बघेले (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुआरा) रहे, जबकि तृतीय स्थान दीपाली साहू (सांदीपनि विद्यालय, सिलवानी) ने प्राप्त किया।

राज्य स्तरीय महोत्सव में सहभागिता करेंगे: आयोजकों ने बताया कि चयनित विद्यार्थी आगामी माह पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मोगली बाल महोत्सव में मध्यप्रदेश के चयनित विद्यार्थियों के साथ सहभागिता करेंगे। प्रतियोगिता के नोडल प्रभारी मयंक रघुवंशी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को परखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

खेल जगत

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बुलंद इरादों से उतरेगा

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में

■ सत्येन्द्र पाल सिंह

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (देशबन्धु)। श्रेयस अय्यर की अगुआई में भारतीय क्रिकेट टीम 2026 एशियाई खेलों में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को शुक्रवार निशीन(जापान) में थोड़े संघर्ष के बाद 19 रन से हरा अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखने के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ नवाबों के शहर लखनऊ में पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के मंगलवार को खेले जाने वाले पहले मैच में बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज से अपना आखिरी टी-20 मैच इस साल के शुरू में आईसीसी टी-20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर आठ में खेला और संजू सैमसन के अविजित 97 रन से कोलकाता के इंडन गार्डन में चार गेंद के बाकी उर्रमें रहते पांच विकेट से जीत दर्ज की।

वेस्टइंडीज के कप्तान अभी शे होप हैं जबकि भारत की कप्तानी अब श्रेयस अय्यर के हाथ में वह खुद को भारत के नए टी-20 क्रिकेट कप्तान के रूप में जुटे हैं। भारत ने वेस्टइंडीज से अपने पांच में तीन जीते और दो हारे हैं और उसके खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखने के मकसद से ही



उतरेगा। संजू सैमसन भारत के लिए एशियाई खेलों में सेमीफाइनल और फाइनल सहित दो मैच खेलने के बावजूद दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सके। भारत के सामने बड़ा सवाल यह रहेगा कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अभिषेक शर्मा और 15 बरस के वैभव सूर्यवंशी से ही पारी का आगाज कराए और संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर बरकरार रखे। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत संतुलित एकादश के साथ उतरेगा। ऐसे में अपने अनुभव और पिछली बेहतरीन पारी

के चलते बहुत मुमकिन है भारत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से पारी का आगाज करा कर वैभव सूर्यवंशी को एकादश से बाहर रखे और तीसरे नंबर तब इशान किशन और चौथे पर कप्तान श्रेयस अय्यर, पांचवें पर तिलक वर्मा और फिर् अल्लारउंडर शिवम दुबे, अक्षर पटेल और नीतिश रेड्डी उतरे। भारत के चीफ कोच गौतम गंभीर का जिस तरह से संजू पर भरोसा है उससे उनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की एकादश में अपनी जगह बरकरार रखने की उम्मीद है।

आईसीसी ने भारत-वेस्टइंडीज टीम पर लगाया जुर्माना

दुबई। न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए तीसरे वनडे मुकाबले में स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए आईसीसी ने भारत और वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना लगाया गया है। शनिवार को हुए आखिरी वनडे में समय की छूट को ध्यान में रखते हुए भारत को चार ओवर और वेस्टइंडीज को दो ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया। इसके बाद भारतीय टीम पर उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत और वेस्टइंडीज पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 (जो न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघनों से संबंधित है) के अनुसार, अगर कोई टीम तय समय में ओवर नहीं फेंक पाती है, तो उसके खिलाड़ियों पर हर ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

भारत की 7 सदस्यीय टीम घोषित भुवनेश्वर कुमार संभालेंगे कमान

हॉंगकांग, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। हॉंगकांग सिक्स 2026 के लिए भारतीय टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के स्टार खिलाड़ियों के साथ उतरेगी। इसमें सात प्रमुख भारतीय क्रिकेटर 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेले जाने वाले तेजतर्रार ‘सिक्स-ए-साइड’ (छह खिलाड़ियों वाले) फॉर्मेट में हिस्सा लेंगे। टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड पर खेले जाने वाली इस लीग में भारतीय टीम की कप्तान अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार संभालेंगे। उनके साथ आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कृणाल पांड्या, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितिश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन भी होंगे। भुवनेश्वर के पास अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल का कई वर्षों का अनुभव है और वे नई गेंद से असरदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, जबकि कृणाल एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर टीम को विविधता देते हैं। नितिश आक्रामक बल्लेबाजी और टॉप ऑर्डर में खेलने का अनुभव लाते हैं। वहीं, शशांक और तेवतिया मैच फिनिश करने की अपनी काबिलियत दिखाते हैं। त्रिपाठी आक्रामक इग्रेदे के साथ खेलते हैं और नटराजन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर एक खास विकल्प देते हैं। टीम इंडिया हॉंगकांग सिक्स में फिर से वापसी करेगी और टूर्नामेंट में आगे तक जाने की कोशिश करेगी। 2025 में उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध डकवर्थ-लुईस नियम से दो रन की जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बाद के मैचों में हार के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इस बार चुनौती कड़ी होगी। पाकिस्तान 2026 के टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतरेगा।

चोट के कारण इस साल कोर्ट पर नजर नहीं आएंगी पोटपोवा

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। दुनिया की 25वें नंबर की खिलाड़ी अनास्तासिया पोटापोवा ने अपने 2026 सीजन को समय से पहले ही खत्म कर दिया है। उन्होंने चोटों से जूझने और करियर की सबसे अच्छी रैंकिंग हासिल करने के मिले-जुले साल के बाद ठीक होने पर ध्यान देने का फैसला किया है।

पोटापोवा ने अपने सोशल मीडिया पर इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर लगातार उन्हें आराम करने का संकेत दे रहा था। उन्होंने ‘इंस्टाग्राम’ पर लिखा, ‘मेरा सीजन खत्म हो रहा है। दुर्भाग्य से, हाल ही में मेरा शरीर मुझे बार-बार संकेत दे रहा है



कि अब रुकने का समय आ गया है। मेरे लिए यह सबसे साफ संकेत है कि मुझे ब्रेक लेने, अपने शरीर को ठीक होने के लिए जरूरी समय देने और मजबूती से वापसी करने की जरूरत है। 2027 में मिलते हैं। ‘पोटापोवा ने यह घोषणा बीजिंग टूर्नामेंट में सिन्जा क्रॉस के खिलाफ अपने शुरुआती दौर के मैच से दाहिने कंधे की चोट के कारण हटने

शरीर को आराम की जरूरत: अनास्तासिया पोटापोवा

के कुछ दिनों बाद की है। उन्हें इसके बाद लुहान में खेलना था, लेकिन अब वह नए सीजन के लिए पूरी तरह फिट होने पर ध्यान देंगी। इस फैसले के साथ ही उस सीजन का समापन हो गया जिसमें पोटापोवा ने रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने साल की शुरुआत लिज्न से पहले 97वें स्थान पर रहते हुए की थी, लेकिन धीरे-धीरे रैंकिंग में ऊपर चढ़ती गई और आखिरकार करियर की सर्वश्रेष्ठ 25वां रैंकिंग तक पहुंचीं, जो अभी भी उनकी मौजूदा रैंकिंग है। उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन क्ले कोर्ट पर रहा।

वैंकूवर, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। टोरेटो सिक्सर्स ने सोमवार को यहाँ मशहूर बीसी प्लेस में खेले गए पुरुषों के फाइनल में वैंकूवर एंक्स को पांच विकेट से हराकर कनाडा सुपर 60 खिताब जीता। यह टोरेटो की दोहरी जीत है। वह इससे पहले महिलाओं की चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं।

जहीर खान की सह-मालिकाना हक वाली टीम वैंकूवर एंक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 164 का स्कोर बनाया। ओबस पीनार ने 21 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए और कप्तान मोईन अली ने 18 गेंदों पर 45 रन जोड़े, लेकिन टोरेटो ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट पर 168 रन बनाकर जीत हासिल की। एंक्स ने धमाकेदार शुरुआत की; एनयूरिन डोनाल्ड ने नौ गेंदों पर 17 रन बनाए और एरॉन जॉनसन ने 10 गेंदों पर 14 रन जोड़े। मार्टिन एंड्रसन के शून्य पर आउट होने



के बाद, मोईन और पीनार ने पारी संभाली और दोनों ने मिलकर 21 बाउंड्री लगाईं। पीनार के 82 रन सिर्फ 21 गेंदों पर आए, जिसमें दो चौके और 12 छक्के शामिल थे, जबकि मोईन के 45 रनों में दो चौके और पाँच छक्के शामिल थे। वैंकूवर ने 16.40 के रन रेट से 164/3 का स्कोर बनाया। टोरेटो की ओर से लक्ष्य का पीछा निकोलस पून ने किया, जिन्होंने 23 गेंदों पर 67 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और नौ छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ भी चुना गया। 291.30 रहा। कीरोन पोलार्ड ने 13 गेंदों

एशियन गेम्स : वैश्विक खेल मंच पर चमके भारत के सितारे

■ विश्वास कैलाश सांरग

जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा की चमक को पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और जज्बे का शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती खेल शक्ति का परिचय कराया। तिरिगे की आन, अब और शान के लिए मैदान में उतरे हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत को गौरवपूर्ण चौथा स्थान दिलाया। यह उपलब्धि केवल पदकों की संख्या नहीं बल्कि भारत की युवा खेल प्रतिभा के निरंतर निरखते सामर्थ्य और वैश्विक खेल मंच पर बढ़ते प्रभाव की स्वर्णिम चमक है। वहीं इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 मेडल जिनमें 5 स्वर्ण, 4 रजत 1 कांस्य पदक अर्जित कर अपनी सर्वोच्च प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विशेष योगदान दिया है।

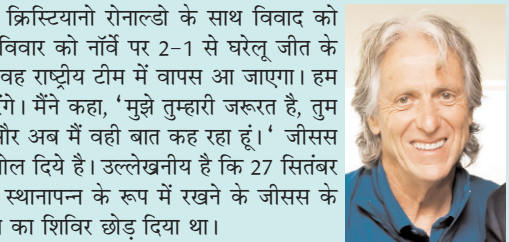
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज खेल भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं केंद्रीय खेल

मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में खेलो इंडिया जैसी योजना के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने, प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके पास अब केवल प्रतिभा नहीं बल्कि उसे निखारने के लिए अवसर, प्रशिक्षण और प्रतियस्पर्धी वातावरण भी उपलब्ध हो रहा है। मध्यप्रदेश में भी हम प्रधानमंत्री के विजन को दृष्टिांत रखते हुए एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान के उन्नयन व विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमी संचालित हैं। इन अकादमियों में विश्व स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। नवीन सीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना के तहत प्रदेश की सभी 230 विधानसभा में खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स, पार्थ योजना, खेलो बढ़ो अभियान, टैलेंट सर्च, समर कैंप सहित अन्य आयोजनों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की तलाश और उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर विश्व पटल पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। भारत के कुल पदकों में एथलेटिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें कुल 24 पदक जीते गए। इसके बाद शूटिंग का नंबर रहा, जिसमें 15 पदक मिले। इनमें तीन बार खिलाड़ी टॉप पोडियम पर रहे। बॉक्सिंग में भी 3 स्वर्ण पदक मिले, जिनमें लक्वीना बोरोहोम भी शामिल थीं। आचरी में सबसे ज्यादा 5 बार खिलाड़ी शोर्ष पोल्ट्रियम पर रहे। अमन सहरावत और सुजीत कलकल ने रसलिंग में एशियन गेम्स चैंपियन का खिताब जीता। भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। नीरू ढांडा, कुमकुम मोहोद, गुलवीर सिंह और विथ्या रामराज जापान में भारत के प्रमुख प्रदर्शन करने वाले एथलीट में शामिल रहे, जिन्होंने कई पदक जीतने में योगदान दिया।

वहीं मध्यप्रदेश के खिलाड़ी भी इस गौरवमयी उपलब्धि में अहम योगदान दिया। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने शूटिंग (शॉटगन) के वुमंस ट्रैप इंडिविजुअल में स्वर्ण, ट्रैप मिक्सड टीम में स्वर्ण और वुमंस

लिस्बन। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कोच जॉर्ज जीसस ने स्टार खिलाड़ी के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ विवाद को गलतफहमी करार देते कहा है कि उनके लिए राष्ट्रीय टीम के दरवाजे खुले हैं। रविवार को नॉर्वे पर 2-1 से धरलू जीत के बाद जीसस ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर वह चाहेगा, तो वह राष्ट्रीय टीम में वापस आ जाएगा। हम अगले कॉल-अप से पहले बात कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्रिस ही करेंगे। मैंने कहा, ‘मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे करीब रहो, चाहे तुम खेल रहे हो या नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है।’ और अब मैं वही बात कह रहा हूं।’ जीसस के इस बयान ने रोनाल्डो के लिए पुर्तगाल की राष्ट्रीय में वापसी के रास्ते खोल दिये है। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर को नेशंस लीग में नॉर्वे के खिलाफ 2-1 से मिली जीत में रोनाल्डो की एक स्थानापन्न के रूप में रखने के जीसस के फैसले ने सार्वजनिक विवाद को जन्म दिया। इसके बाद रोनाल्डो ने पुर्तगाल टीम का शिविर छोड़ दिया था।



वैभव को अपने मौके का इंतजार करना होगा : गंभीर

■ सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने



नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है। गंभीर ने कहा कि उन्होंने 15 वर्षीय खिलाड़ी को समझाया कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, कभी-कभी खिलाड़ी को अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है। इस साल जुलाई में सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। उन्होंने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद, वह पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 साल और 118 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। हालाँकि, उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज और एशियन गेम्स से पहले जापान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला। 15 साल के इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी की, जहां उन्होंने 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर मैच में अहम भूमिका निभाई। गंभीर ने ‘जियोस्टर’ पर कहा, ‘यह मेरे लिए भी एक नया अनुभव था। हां, वह अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी, उन खिलाड़ियों की वजह से जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है। एक और बात,

सोशल मीडिया या बाहर की बातें प्लेइंग इलेवन तय नहीं करतीं। भारतीय मुख्य कोच ने आगे कहा, ‘यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रैसिंग रूम का समीकरण कैसा है, कौन सा खिलाड़ी कोच और कप्तान को मैच जिताने की क्षमता रखता है, तथा टीम की सबसे मजबूत ‘प्लेइंग इलेवन’ क्या है। इसके साथ ही यह भी देkhना होता है कि किसने लंबे समय तक लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आज हम वैभव को मौका देते हैं, तो मेरे और टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ी- चाहे वह अभिषेक हों या संजू सैमसन के बीच बातचीत काफी मुश्किल होगी। ‘उन्होंने आगे कहा, ‘यही वजह है कि हम अचानक उस टीम संयोजन (कॉम्बिनेशन) को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसने पिछले डेढ़-दो साल में शानदार प्रदर्शन किया है। लगातार तीन-चार मैचों में असफल होने पर हम अनुभवी खिलाड़ियों को ड्रॉप करके किसी ऐसे युवा को टीम में शामिल नहीं कर सकते, जो भले ही बेहद प्रतिभाशाली और बेहतरीन फॉर्म में हो। खिलाड़ियों को कभी-कभी अपने मौके का इंतजार करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रैसिंग रूम में सुरक्षा और निरंतरता का माहौल बनाए रखना है।

सार संक्षेप

ब्राजील से मिली हार के बाद भारत के सामने उरुग्वे की कड़ी चुनौती

कोलकाता। ब्राजील से 0-4 की हार से उबरने के लिए भारत के पास बहुत कम समय है उसे अब मंगलवार को यहां फीफा अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे जैसी मजबूत टीम का सामना करना है। पनामा के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ मैच ने खालिद जमील की टीम के लिए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन शनिवार को साउट लेक स्टेडियम में ब्राजील ने भारत और दुनिया की टॉप टीमों के बीच कौशल का अंतर दिखा दिया। भारत को अब उस हार को पीछे छोड़कर उरुग्वे के खिलाफ मुकाबला करने का तरीका खोजना होगा, जो दुनिया में 20वें नंबर पर है। बड़ी हार के बावजूद, जमील को अपनी टीम के प्रदर्शन में कुछ सकारात्मक बातें दिखीं, खासकर उनकी पॉसिंग, डिफेंस का तालमेल और शुरुआती 25 मिनट में काउंटर-अटैक करने की कोशिशें। ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने भी उन क्षेत्रों में भारत की कोशिशों को माना। भारत को उन पलों को आगे बढ़ाना होगा, खासकर ऐसी टीम के खिलाफ जिसके पास बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। दुनिया में 138वें नंबर की टीम के लिए, उरुग्वे के खिलाफ गोल कराना या मैच ड्रॉ कराना भी एक बड़ी उपलब्धि होगी।

न्यूजीलैंड के लिए ‘केजुअल’ कॉन्ट्रैक्ट पर खेलेंगे माइकल ब्रेसवेल

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने 2026-27 सीजन में ऑस्ट्रेलिया की विज बेश लीग (बीबीएल) में खेलने का मौका पाने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ ‘केजुअल’ कॉन्ट्रैक्ट लेने का फैसला किया है। इस कदम से वह दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलने के लिए अधिक उपलब्ध रहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी न्यूजीलैंड की नेशनल टीम के लिए खेलना ही है। 35 वर्षीय ब्रेसवेल उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 2026-27 सीजन के लिए केजुअल कॉन्ट्रैक्ट चुना है। इस सूची में फिन एलन, मार्क चैपमैन, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने और टिम सीफर्ट जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। ब्रेसवेल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने के बाद उनकी जगह बल्लेबाज निक केली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यह केली के करियर का पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो उन्हें अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू के करीब 11 साल बाद मिला है। 33 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है।

नेशंस लीग: पुर्तगाल ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

नई दिल्ली। पुर्तगाल ने यूईएफए नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना खेल रही पुर्तगाल टीम ने 79वें मिनट में गोकालो रामोस के विजयी गोल की मदद से नॉर्वि को 2-1 से हराया। क्रिस्टोफर अजेर ने शानदार हाफ-बॉली के जरिए मेहमान टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन दो मिनट बाद ही जोआओ कैंसेलो ने शानदार अंदाज में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद मेजबान टीम ने बढ़त हासिल कर ली। जोआओ फेलिक्स के शानदार पास पर गोंकालो रामोस ने गोल दागा। दो बार नेशंस लीग का खिताब जीत चुकी पुर्तगाल की टीम ने मैच के अंत तक अपनी बढ़त कायम रखी और ग्रुप ए4 में जीत का सिलसिला जारी रखा। हालांकि, मैच के आखिरी मिनटों में फ्रांसिस्को कॉन्विकाओ को दूसरा पीना कार्ड मिलने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे टीम की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा।



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री

सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026

युवा सोच, नये अवसर, एक साझा मंच

प्रख्यात गायक
जुबिन नौटियाल
एवं कबीर कैफे बैंड
द्वारा
भव्य लाइव प्रस्तुति
प्रातः 10:00 बजे

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
के साथ

6 अक्टूबर, 2026 | पूर्वाह्न 11:00 बजे
लाल परेड ग्राउंड, भोपाल

70+ स्टॉल, 15 विभागों की संयुक्त भागीदारी

युवाओं को अवसर, कौशल,
रोज़गार, नवाचार एवं
संभावनाओं से जोड़ने हेतु
समर्पित मंच

स्टार्टअप एवं उद्यमिता

युवा उद्यमियों के
फार्मास्युटिकल, मैनुफैक्चरिंग,
AI/मशीन लर्निंग और फूड
प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स
की सहभागिता एवं प्रस्तुति

युवा नवाचार एवं प्रदर्शनी

AI, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन
टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं
नवाचार, कृषि क्षेत्र में रोज़गार,
फ्यूचर रेडी एजुकेशन और
टेक्नोलॉजी पर केन्द्रित

सार्वजनिक एवं निजी विश्वविद्यालयों की सहभागिता

विश्वविद्यालयों द्वारा कैरियर
मार्गदर्शन, नवाचार, उद्यमिता,
तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार के
अवसरों की जानकारी

कैरियर एवं कौशल के अवसर

कौशल विकास, कैरियर
मार्गदर्शन और रोज़गार से जुड़ी
जानकारी एक ही स्थान पर

शासकीय योजनाओं की जानकारी

पात्रता, पंजीयन, आवेदन
प्रक्रिया, प्रशिक्षण और उपलब्ध
सुविधाओं से संबंधित स्टॉल



सीधा

प्रसारण



@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh



@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP



JansamparkMP